



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 361]
No. 361]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 15, 1984/भाद्र 24, 1906
NEW DELHI, SATURDAY, SEPT. 15, 1984/BHADRA 24, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वाणिज्य दफ्तर

(टेक्सटाइल विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1984

जूट विनिमिति विकास परिषद् (प्रक्रियात्मक) नियम, 1984

सा.का.नि. 658(अ) :—केन्द्रीय सरकार, जूट विनिमिति विकास परिषद् अधिनियम, 1983 (1983 का 27) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम :—इन नियमों का संक्षिप्त नाम जूट विनिमिति विकास परिषद् (प्रक्रियात्मक) नियम, 1984 है।

2. प्रारम्भ :—ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3. परिभाषाएं :—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से जूट विनिमिति विकास परिषद् अधिनियम, 1983 (1983 का 27) अभिप्रेत है,

(ख) “उपाध्यक्ष” से अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (5) के अनुसार निर्वाचित परिषद् का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है,

(ग) “सदस्य” से परिषद् का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी हैं,

(घ) “सचिव” से परिषद् के सचिव के कृत्यों को करने के लिए इन नियमों के नियम 6 के अधीन नियुक्त परिषद् का प्रधान अधिकारी अभिप्रेत है,

(ङ) “जूट निधि” से अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन सजित निधि अभिप्रेत है।

4. अध्यक्ष की शक्तियाँ और कृत्य :—

(1) अधिनियम और उसके अधीन. विरचित नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अध्यक्ष परिषद के दिन प्रति-दिन के कार्य के लिए उत्तरदायी होगा।

5. उपाध्यक्ष की शक्तियाँ और कृत्य :—

(1) उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, परिषद के अधिवेशनों में सभापतित्व करेगा।

(2) यदि उपाध्यक्ष के त्यागपत्र के कारण या उसके सदस्य न रह जाने के कारण या अन्यथा उसके पद में कोई आकस्मिक रिक्ति होती है, तो परिषद अपने अगले अधिवेशन में अन्य सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करेगी जो भूतपूर्व उपाध्यक्ष की पदावधि की अपर्यवसित कालावधि के लिए पद धारण करेगा।

6. सचिव की शक्तियाँ और कर्तव्य :—

(1) सचिव की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से परिषद द्वारा की जाएगी।

(2) सचिव परिषद का प्रधान अधिकारी होगा और अध्यक्ष के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा।

(3) सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह :—

- (i) परिषद द्वारा लिए गए सभी विनिश्चयों को कार्यान्वित करे,
- (ii) परिषद के अन्य अधिकारियों और स्थापनों के कार्य का ममन्वय और पर्यवेक्षण करे,
- (iii) अध्यक्ष के निदेशानुसार परिषद के अधिवेशनों का संयोजन करे,
- (iv) परिषद द्वारा किए गए कामकाज का अभिलेख रखने वाली कार्यवृत्त अनुरक्षित करे,
- (v) केन्द्रीय सरकार को ऐसी सभी रिपोर्टें/विवरणियाँ और अन्य आवश्यक दस्तावेजों जिनका अधिनियम द्वारा उस सरकार को दिया जाना अपेक्षित है, दे,
- (vi) प्रत्येक वर्ष परिषद के अनुमोदन के लिए परिषद के बजट प्राक्कलन और लेख तैयार करे,
- (vii) ऐसी शक्तियों के अधीन जो परिषद समिति द्वारा प्रत्यायोजित की जाएँ और ऐसी सीमाओं के भीतर जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएँ, अनुदानों के पुनर्विनियोग को मंजूर करे,
- (viii) परिषद के भविष्य निधि को प्रणामित करे,
- (ix) ऐसे अन्य कर्तव्य करे और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करे जो समय समय पर परिषद या अध्यक्ष द्वारा उसे सौंपे जाएँ या प्रत्यायोजित किए जाएँ।

7. सदस्य की नियुक्ति की अवधि :—

(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिषद का सदस्य दो वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेगा।

(2) केन्द्रीय सरकार के लिए अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन नियुक्त किसी सदस्य के स्थान पर दो वर्ष पूरे किए जाने से पूर्व किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति करना सक्षम होगा यदि उसकी यह राय हो कि ऐसा सदस्य ऐसे हितों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है जिसका प्रतिनिधित्व करने के लिए उसकी नियुक्ति की गई थी।

8. सदस्य का त्यागपत्र :—

(1) परिषद का सदस्य परिषद के अध्यक्ष को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर से पत्र लिखकर अपने पद का त्याग कर सकेगा।

(2) सदस्य का पद उस तारीख से जिसको उसका त्यागपत्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है या त्यागपत्र की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन की समाप्ति पर, इन दोनों में से जो भी पहले हो, रिक्त हो जाएगा।

9. भारत से सदस्य की अनुपस्थिति :—

(1) यदि कोई सदस्य एक मास से अधिक के लिए भारत से प्रस्थान करना चाहता है, तो वह अध्यक्ष को अपने प्रस्थान की तारीख और भारत में अपनी प्रत्याशित वापसी की तारीख संसूचित करेगा और यदि ऐसा सदस्य छह मास से अधिक की कालावधि के लिए भारत से अनुपस्थित रहना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र दे देगा।

10. सदस्यता का न रह जाना :—

(1) यदि कोई सदस्य अध्यक्ष की इजाजत के बिना परिषद के तीन क्रमवर्ती अधिवेशनों में उपस्थित होने में असफल रहता है, तो वह सदस्य नहीं रह जाएगा।

(2) कोई सदस्य तब सदस्य नहीं रह जाएगा, —

- (i) यदि वह विकृतचित हो जाता है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया जाता है, या
- (ii) यदि वह अनुमोचित डिवालिया है, या
- (iii) उसे ऐसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्बलित है।

11. सदस्यों की आकस्मिक रिक्ति का भरा जाना :—

(1) परिषद की सदस्यता में किसी भी कारण से होने वाली किसी आकस्मिक रिक्ति को केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्ति द्वारा भरा जायेगा।

(2) आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त सदस्य पद तब तक धारण करेगा जब तक वह सदस्य जिसका

स्थान उसने भरा है, पद धारण करने के लिए हकदार होता यदि रिक्ति न हुई होती।

12. प्रतिस्थानी की नियुक्ति :—यदि परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति परिषद के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने से निवारित हो जाता है, तो उसका स्थान लेने के लिए प्रतिस्थानी की केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्ति की जा सकेगी। ऐसे प्रतिस्थानी को केवल उस अधिवेशन के लिए सदस्य के रूप में अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे।

13. पते में परिवर्तन :—

सदस्य अपने पते में हुए किसी परिवर्तन की जानकारी सचिव को देता रहेगा और अपने पते में किसी परिवर्तन की जानकारी देने में असफल रहने पर पहली बार दिया गया पता सही प्रयोजनों के लिए उसका सही पता माना जाएगा।

14. परिषद् के अधिवेशनों के लिए प्रक्रिया :—

(1) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में परिषद के कम से कम एक अधिवेशन का आयोजन अवश्य किया जाएगा।

(2) अध्यक्ष किसी भी समय परिषद के अधिवेशन का संयोजन कर सकेगा :

परन्तु अध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह परिषद के अधिवेशन का उक्त दशा में संयोजन करे, यदि ऐसे अधिवेशन के लिए अध्यापेक्षा कम से कम 11 सदस्यों द्वारा लिखित रूप में उसे प्रस्तुत की जाए।

परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार के लिए यह मक्षम होगा कि वह किसी भी समय अधिवेशन का संयोजन करने की अध्यक्ष से अपेक्षा करे।

परन्तु यह और कि आपात मामलों में, अध्यक्ष द्वारा किसी भी समय विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकेगा, जो भारत सरकार और सदस्यों की विचारार्थ विषयों के बारे में और उन कारणों के बारे में अग्रिम जानकारी देगा जिनके लिए वह इसे अत्यावश्यक समझता है। ऐसे विशेष अधिवेशन में कोई अन्य कामकाज नहीं किया जाएगा।

(3) सचिव, अध्यक्ष के अनुमोदन से या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष के अनुमोदन से परिषद के प्रत्येक अधिवेशन की तारीख, समय और स्थान नियत करेगा और कम से कम दस दिन की स्पष्ट सूचना देने हुए अधिवेशन की सूचना जारी करेगा।

(4) सचिव, अध्यक्ष के अनुमोदन से या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष के अनुमोदन से परिषद के किसी अधिवेशन के कम से कम सात दिन पूर्व, ऐसे अधिवेशन में होने वाले कामकाज की एक सूची तैयार करेगा और उसे सदस्यों में परिचालित करवायेगा। ऐसे किसी

कामकाज पर जो कार्य सूची में सम्मिलित नहीं है, अधिवेशन के अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना परिषद के अधिवेशन में विचार नहीं किया जाएगा। यदि कोई सदस्य परिषद द्वारा विचार किए जाने के लिए किसी विषय का सुझाव देना चाहता है तो वह कम से कम दस दिन की स्पष्ट सूचना देगा।

(5) अध्यक्ष, या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष परिषद के अधिवेशनों में सभापतित्व करेगा, परन्तु जहाँ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों, वहाँ उपस्थित सदस्य अधिवेशन का सभापतित्व करने के लिए आपस में से एक सदस्य को निर्वाचित करेंगे।

(6) परिषद के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई सदस्यों से किन्तु उपस्थित कम से कम सात सदस्यों से परिषद के अधिवेशन में गणपूर्ति का गठन होगा।

(7) किसी अधिवेशन में उपस्थित परिषद के सदस्यों के बीच मतभेद होने की दशा में बहुमत अभिभावी होगा। परिषद के प्रत्येक सदस्य को एक मत का अधिकार होगा। मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या दोनों की अनुपस्थिति में ऐसे अधिवेशन का सभापतित्व करने वाले सदस्य को द्वितीय या निर्णायक मत प्राप्त होगा।

(8) ऐसा कोई प्रस्ताव, जिस पर परिषद द्वारा विचार करना अपेक्षित है, इसके सभी सदस्यों को या तो उसके अधिवेशन में या उसके सभी सदस्यों में परिचालन द्वारा निर्देशित किया जा सकेगा और इस प्रकार परिचालित और बहुसंख्यक सदस्यों द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव उतना ही प्रभावशाली और आबद्धकर होगा मानों ऐसा प्रस्ताव परिषद के किसी अधिवेशन में पारित किया गया हो।

परन्तु यह तब जबकि परिषद के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई सदस्यों ने प्रस्ताव पर अपने विचार अभिलिखित किए हैं। जब कागज पत्रों के परिचालन द्वारा कामकाज किया जाता है, तो इस प्रकार किए गए कामकाज के अभिलेख पर परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जायेंगे।

(9) परिषद द्वारा किए गए सभी कामकाज का अभिलेख बनाए रखा जाएगा और ऐसे अभिलेख की प्रतियां केन्द्रीय सरकार को भेजी जायेंगी। परिषद के अधिवेशन में किए गए कामकाज के अभिलेख पर ऐसे अधिवेशन का सभापतित्व करने वाले अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जायेंगे।

15. कार्यों और कार्यवाहियों की विधिमान्यता :

परिषद का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अधिमान्य या प्रणतगत नहीं होगी कि परिषद के गठन में कोई रिक्ति या उसमें कोई वृत्ति है।

16. परिषद की शक्तियाँ :

(1) नियुक्ति की शक्ति :—

अधिनियम की धारा 6 के उपबंधों के अधीन रहते हुए परिषद ऐसे नये पद सजित कर सकेगी और उसमें नई नियुक्तियाँ कर सकेगी जो उसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए आवश्यक हों, परन्तु 1300 रु० प्रतिमास से अधिक के अधिकतम बतन वाले कोई पद केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना न तो सजित किए जाएंगे और न भरे जायेंगे।

(2) अन्य शक्तियाँ :

(i) नियम 18 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिषद अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में निधि से किसी व्यय को संकल्प द्वारा मंजूर कर सकेगी या ऐसा संविदा कर सकेगी जिसमें वह व्यय अन्तर्बलित हों :

परन्तु परिषद बजट प्राक्कलन से अधिक कोई व्यय मंजूर नहीं करेगी या कोई ऐसा संविदा नहीं करेगी जिसमें वह व्यय अन्तर्बलित है :

परन्तु यह और कि परिषद केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, ऐसा कोई संविदा नहीं करेगी जिसमें दो लाख रुपये से अधिक का व्यय अन्तर्बलित है या जो पांच वर्ष की कालावधि तक का है।

(ii) परिषद को किसी व्यक्तिगत मामले में पांच हजार रुपये तक की हानियों को माफ करने की शक्ति होगी।

(iii) परिषद नियम 18 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक व्यक्तिगत मद पर उतनी रकम का जो 10,000 रु० से अधिक की नहीं है, भारत के बाहर व्यय उपगत कर सकती है।

17. सदस्यों का रजिस्टर :—

(1) सचिव एक रजिस्टर बनाये रखेगा जिसमें परिषद के प्रत्येक सदस्य का नाम और पता लिखा जायेगा।

(2) समिति के सदस्यों के नाम और पते एक पुथक रजिस्टर में रखे जायेंगे।

(3) यदि परिषद का या उसकी किसी समिति का कोई सदस्य अपने पते में कोई परिवर्तन करता है तो वह अपने नये पते की सूचना सचिव को देगा और तदनुसार सचिव रजिस्टर में की सुसंगत प्रविष्टि में संशोधन करेगा।

18. वार्षिक बजट प्राक्कलन :—

(क) तैयार किया जाना और प्रस्तुत किया जाना—

परिषद प्रत्येक वर्ष ऐसी रीति में जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्देशित करे, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए

बजट प्राक्कलन और चालू वर्ष के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार करेगी और उन्हें ऐसी तारीखों को या उनसे पूर्व जो उस सरकार द्वारा नियम की जायें, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगी। केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित बजट वर्ष के लिए स्वीकृत बजट होगा।

(ख) पुनर्विनियोग :

(i) यदि परिषद वर्ष के अनुक्रम में यह पाती है कि किसी शीर्ष के अधीन स्वीकृत बजट प्राक्कलन से अधिक व्यय के होने की संभावना है तो वह अन्य शीर्ष के अधीन संभाव्य वचन मालूम करे और पुनर्विनियोग करने के उद्देश्य से बजट प्राक्कलन के प्रत्येक शीर्ष के अधीन आबंटन की जांच करेगी। जहाँ ऐसा पुनर्विनियोग संभव है वहाँ वह ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिकथित की जाएं, पुनर्विनियोग स्वीकृत कर सकेगी।

(ii) निधियों का केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी नई सेवाओं पर जो बजट प्राक्कलन में अनुज्ञात नहीं है, व्यय की पूर्ति करने के लिए पुनर्विनियोग नहीं किया जाएगा।

19. परिषद के बैंक लेखाओं और निधियों के विनिधान का अनुरक्षण और प्रचालन :—

(1) परिषद द्वारा प्राप्त सभी धन यथासंभव शीघ्र भारतीय स्टेट बैंक या ऐसे अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में जो परिषद द्वारा अनुमोदित किए जाएं जमा कर दिया जाएगा और उसका उपयोजन अधिनियम के प्रयोजनों से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।

(2) परिषद द्वारा या उसकी ओर से सभी संदाय सचिव की विशेष स्वीकृति के अधीन ऐसी रकमों के सिवाय जो साधारणतया 1,000 रुपये और असाधारणतया 2,500 रु० से अधिक नहीं हैं, जिन्हें नकद रूप में दिया जा सकेगा, बैंक द्वारा किये जाएंगे।

(3) ऐसे बैंकों पर और निक्षेप या विनिधान करने वाले या उसे वापस निकालने वाले सभी आदेशों पर सचिव या मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा या परिषद द्वारा इस निमित्त किन्हीं दो अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(4) परिषद की निधियों में से तब तक कोई संदाय नहीं किया जाएगा जब तक कि व्यय स्वीकृत बजट के अन्तर्गत न आता हो।

(5) परिषद द्वारा सभी संदाय सचिव या परिषद द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से तैयार किए गए और पारित बिलों या अन्य दस्तावेजों पर ही किये जायेंगे। संवत् वाउचर पर "संवत्" की मोहर लगा दी जाएगी या उसे इस प्रकार रद्द किया जाएगा कि दूसरी बार उसका उपयोग न किया जा सके।

(6) ऐसी सभी निधियों जो चालू व्यय के लिए अपेक्षित नहीं हैं, ऐसे बैंकों में जो केन्द्रीय सरकार अनुमोदित हों, सावधि निक्षेप में जमा की जाएंगी। सावधि निक्षेप में जमा करने और इस प्रकार जमा धन के व्ययन के लिए अध्यक्ष की या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष की स्वीकृति अपेक्षित होगी।

20. व्यक्तियों को विदेश भेजना.—परिषद केन्द्रीय सरकार की पूर्व मजूरी के बिना परिषद के किसी सदस्य या अपने किसी अधिकारी या कर्मचारी को भारत के बाहर स्थानों नहीं भेजेगी।

[फा.सं. 5/16/83-ईपी (टीजे)-3]

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Textiles)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 1984

The Jute Manufactures Development Council (Procedural) Rules, 1984

G.S.R. 658(E).—In exercise of the powers conferred by section 25 of the Jute Manufactures Development Council Act, 1983 (27 of 1983), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title:—These rules may be called the Jute Manufactures Development Council (Procedural) Rules, 1984.

2. Commencement.—They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) "Act" means the Jute Manufactures Development Council Act, 1983 (27 of 1983);
- (b) "Vice-Chairman" means the Vice-Chairman of the Council elected in accordance with sub-section (5) of section 3 of the Act;
- (c) "member" means a member of the Council and includes the Chairman and the Vice-Chairman;
- (d) "Secretary" means the principal officer of the Council appointed under rule 6 of these rules to carry on the functions of Secretary of the Council;
- (e) "Jute Fund" means the fund created under sub-section (1) of section 10 of the Act.

4. Powers and Functions of the Chairman.—(1) Subject to the provisions of the Act and the rules framed thereunder, the Chairman shall be responsible for the day to day functioning of the Council.

5. Powers & functions of the Vice-Chairman.—(1) The Vice-Chairman shall preside over the meetings of the Council in the absence of the Chairman.

(2) If a casual vacancy occurs in the office of the Vice-Chairman on account of his resignation or his ceasing to be a member or otherwise, the Council shall elect at its next meeting another member as the Vice-Chairman who shall hold office for the unexpired period of the term of office of the previous Vice-Chairman.

6. Powers and duties of the Secretary.—(1) The Secretary shall be appointed by the Council with the approval of the Central Government.

(2) The Secretary shall be the principal officer of the Council and shall work under the supervision of the Chairman.

(3) It shall be the duty of the Secretary to :—

- (i) implement all decisions taken by the Council;
- (ii) co-ordinate and supervise the work of the other officers and the establishments of the Council;
- (iii) convene under the directions of the Chairman meetings of the Council;
- (iv) maintain the minute books containing a record of the business transacted by the Council;
- (v) furnish to the Central Government all reports, returns and other necessary documents required to be furnished to that Government by the Act;
- (vi) prepare every year the Budget Estimates and Accounts of the Council for the Council's approval;
- (vii) sanction re-appropriation of grants under such powers as may be delegated by the Council and within such limits as may be specified by it;
- (viii) administer the Provident Fund of the Council;
- (ix) undertake such other duties and exercise such other powers, as may, from time to time, be entrusted or delegated to him by the Council or the Chairman.

7. Tenure of appointment of member.—(1) Subject to the provisions of sub-rule (2), a member of the Council shall hold office for a period of two years.

(2) It shall be competent for the Central Government to appoint another person in the place of a member appointed under sub-section (4) of section 3 of the Act before the completion of two years if it is of opinion that such member has ceased to represent the interests he was appointed to represent.

8. Resignation of member.—(1) A member of the Council may resign his office by writing a letter under his hand addressed to the Chairman of the Council.

(2) The office of a member shall fall vacant from the date on which his resignation is accepted by the Government or on the expiry of 30 (thirty) days from the date of receipt of resignation, whichever is earlier.

9. Absence of members from India.—If a member intends to leave India for more than one month, he shall intimate the Chairman the date of his departure and the date of his expected return to India and if such member intends to be absent from India for a period longer than 6 (six) months he shall tender his resignation.

10. Cessation of membership.—(1) A member shall cease to be a member if he fails to attend three consecutive meetings of the Council without leave of the Chairman.

(2) A member shall cease to be a member,—

- (i) if he becomes of unsound mind and is declared so by a competent Court, or
- (ii) if he is an undischarged insolvent, or
- (iii) if he is convicted of an offence involving moral turpitude.

11. Filling of casual vacancy of members.—(1) Any casual vacancy in the membership of the Council by any reason shall be filled by appointment by the Central Government.

(2) A member appointed to fill a casual vacancy shall hold office for so long as the member, whose place he fills, would have been entitled to hold office if the vacancy had not occurred.

12. Appointment of substitutes.—Should a person, appointed as member of the Council, be prevented from attending a meeting of the Council, a substitute to take his place may be appointed by the Central Government. Such substitute shall have rights and privileges as a member for that meeting only.

13. Change of address.—A member shall keep the Secretary informed of any change in his address and on failure to inform the change of his address, the address given in the first instance shall for all purposes be deemed to be his correct address.

14. Procedure for meetings of the Council.—(1) Not less than one meeting of the Council shall be held in each financial year.

(2) The Chairman may, at any time, convene a meeting of the Council :

Provided that it shall be the duty of the Chairman to convene a meeting of the Council if a requisition for such meeting is presented to him in writing by at least eleven members :

Provided further that it shall be competent for the Central Government to require the Chairman to convene a meeting at any time :

Provided further that in cases of emergency, a special meeting may be summoned at any time by the Chairman who shall inform in advance the Government of India and members of the subject matter for discussion and the reasons for which he considers it urgent. No other business shall be transacted at such special meeting.

(3) The Secretary shall, with the approval of the Chairman, or, in the absence of the Chairman, the Vice Chairman, fix the date, time and place of every meeting of the Council and issue notice of the meeting giving at least ten clear days' notice.

(4) The Secretary shall, with the approval of the Chairman, or in the absence of Chairman, the Vice-Chairman, prepare and circulate amongst the members, at least seven days before a meeting of the Council, a list of the business to be transacted at such meeting. No business, not included in the Agenda shall be considered at a meeting of the Council, without permission of the Chairman of the meeting. If any member desires to suggest any subject for discussion by the Council, he shall give at least ten clear days' notice.

(5) The Chairman, or in his absence, the Vice Chairman, shall preside over the meetings of the Council :

Provided that where both the Chairman and the Vice-Chairman are absent, the members present shall elect a member from among themselves to preside over the meeting.

(6) One-third of the total number of members of the Council but not less than seven members present shall form a quorum at a meeting of the Council.

(7) In case of difference of opinion amongst the members of the Council present at a meeting, the opinion of the majority shall prevail. Each member of the Council shall have one vote. In case of any equality of votes, the Chairman, or the Vice-Chairman, or in the absence of both, the member presiding over such meeting shall have a second or a casting vote.

(8) Any proposal, which the Council is required to consider, may be referred to all its members either at its meeting or by circulation among all its members and any proposal so circulated and approved by a majority of members shall be as effectual and binding as if such proposal had been passed at a meeting of the Council :

Provided that at least one third of the total number of members of the Council have recorded their views on the proposal. When business is transacted by circulation of papers, a record of business so transacted shall be signed by the Chairman or the Vice-Chairman of the Council.

(9) A record shall be maintained of all business transacted by the Council, and copies of such record shall be submitted to the Central Government. The record of business transacted at a meeting of the Council shall be signed by the Chairman presiding over such meeting.

15. Validity of the acts and proceedings.—No act or proceedings of the Council shall be invalid or questioned on the ground merely of any vacancy in, or any defect in the constitution of the Council.

16. Powers of the Council : (1) Power of appointment.—Subject to the provisions of section 6 of the Act, the Council may create new posts and make appointments thereto as may be necessary for the efficient performance of its functions, provided that no posts carrying the maximum salary beyond Rupees 1,300 per mensem shall be created or filled without the previous approval of the Central Government.

(2) Other Powers :

- (i) Subject to the provisions of rule 18, the Council may, by resolution, sanction any expenditure or enter into any contract involv-

ing expenditure from the Fund in the discharge of its functions under the Act :

Provided that the Council shall not sanction any expenditure or enter into any contract involving expenditure in excess of the budget allotments.

Provided further that the Council shall not enter into any contract involving any expenditure in excess of two lakhs of rupees, or extending over a period of five years, without the previous approval of the Central Government.

(ii) The Council shall have power to write off, in any individual case, losses upto five thousand rupees.

(iii) The Council may incur expenditure outside India upto an amount not exceeding ten thousand rupees on each individual item subject to the provisions of rule 18.

17. Register of members—(1) The Secretary shall maintain a register in which the name and address of each member of the Council shall be entered.

(2) The names and addresses of members of Committees shall be kept in a separate register.

(3) If a member of the Council or any of its Committees changes his address, he shall notify his new address to the Secretary and the Secretary shall amend the relevant entry in the register accordingly.

18. Annual Budget Estimates—

(a) Preparation and submission—

The Council shall in each year prepare, in such manner as the Central Government may from time to time direct, budget estimates for the ensuing financial year and revised estimates for the current year and shall submit them for the approval of the Central Government on or before such dates as may be fixed by that Government. The budget as approved by the Central Government shall be the sanctioned budget for the year.

(b) Re-appropriation—

(i) If the Council finds in the course of the year that there is likely to be an excess of expenditure over the sanctioned budget estimate under any head, it shall examine the allotment under each head of the budget estimate with the object of finding probable savings under any other head and effecting a re-appropriation. Where such re-appropriation is feasible, it may sanction the re-appropriation subject to such conditions as may be laid down by the Central Government from time to time.

(ii) Funds shall not be re-appropriated to meet expenditure on a new service not contemplated in the budget estimates except with the prior approval of the Central Government.

19. Maintenance and operation of Bank Accounts and Investment of Funds of the Council—

(1) All moneys received by the Council shall as soon as possible be deposited in the State Bank of India or such other Nationalised Banks as may be approved by the Council, and shall not be utilised for any purpose other than the purposes of the Act.

(2) All payments by or on behalf of the Council shall be made by cheques except for amounts not exceeding ordinarily Rs. 1000 and extraordinarily Rs. 2500 under special sanction of the Secretary, which may be paid in cash.

(3) Such cheques and all orders for making deposits or investments or for the withdrawal of the same shall be signed jointly by the Secretary and by the chief accounts officer, or by any two officers authorised by the Council, in this behalf.

(4) No payment shall be made out of the funds of the Council unless the expenditure is covered by the sanctioned budget.

(5) All payments by the Council shall be made on bills or other documents duly prepared and passed by the Secretary or other officer authorised by the Council in this behalf. The paid vouchers shall be stamped "Paid" or so cancelled that they cannot be used a second time.

(6) All funds not required for current expenditure may be placed in fixed deposit with such Banks as the Central Government may approve. The placing of money in fixed deposit and the disposal of money so placed shall require the sanction of the Chairman or in his absence, the Vice-Chairman.

20. Sending persons abroad—The Council shall not send any member of the Council or any of its officers or employees to places outside India without the previous sanction of the Central Government.

[F. No. 5/16/83-EP(T&J)III]

J. K. BAGCHI, Jt. Secy.

अधिसूचना

जूट विनियम, उपकर नियम, 1984

सा० का० नि० 659 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, जूट विनियम उपकर अधिनियम, 1983 (1983 का 28) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जूट विनियम उपकर नियम, 1984 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं : इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) "अधिनियम" से जूट विनिमिति उपकर अधिनियम, 1983 (1983 का 28) अभिप्रेत है ;
- (ख) "उपकर" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उद्घाटित उत्पाद-शुल्क अभिप्रेत है ;
- (ग) "कलक्टर" से केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के अधीन नियुक्त किया गया केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, कलक्टर अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अतिरिक्त कलक्टर, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उप-कलक्टर, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक कलक्टर और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधीक्षक भी हैं ;
- (घ) "आयुक्त" से भारत सरकार का जूट आयुक्त अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत जूट आयुक्त के कार्यालय में के जूट उपायुक्त, औद्योगिक सलाहकार और उपनिदेशक भी हैं ;
- (ङ) जूट की किसी विनिमिति के संबंध में, "उत्पादक" से ऐसी जूट विनिमितियों का उत्पादक अभिप्रेत है ;
- (च) "परिषद्" से जूट विनिमिति विकास परिषद् अधिनियम, 1983 (1983 का 27) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित की गई जूट विनिमिति विकास परिषद् अभिप्रेत है ;
- (छ) "जूट निधि" से जूट विनिमिति विकास परिषद् अधिनियम, 1983 (1983 का 27) की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन सृजित निधि अभिप्रेत है ;
- (ज) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) या उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित हैं, वही अर्थ हैं जो उनके उस अधिनियम या उन नियमों में क्रमशः हैं ।

3. उपकर की दर : उपकर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम के अनुसार समय-समय पर विनिर्दिष्ट की गई दर पर ऐसी तैयार जूट विनिमितियों पर देय होगा जो विक्रय तदनन्तर विक्रय के लिए उत्पादक द्वारा देश के बाहर निर्यात के लिए और या देश के भीतर वितरण और उपभोग के लिए हटाई जाती हैं ।

4. निर्यात मंडे उपकर का प्रतिदाय न किया जाना : भारत के बाहर निर्यात की गई जूट विनिमितियों पर उपकर का कोई प्रतिदाय अनुज्ञात नहीं होगा ।

5. रजिस्ट्रों का रखा जाना : प्रत्येक उत्पादक एक उत्पादन रजिस्टर रखेगा जिसमें किसी मास के दौरान उसके द्वारा विनिर्मित जूट विनिमितियों की कुल मात्रा, किसी अन्य

वस्तु के विनिर्माण के लिए उसके द्वारा प्रयोग में लाई गई मात्रा (यदि कोई है), केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के अधीन शुल्क का संदाय करके हटाई गयी मात्रा, ऐसे शुल्क का संदाय किए विनिर्माण के लिए हटाई गई मात्रा, मूल्यानुसार कुल मूल्य जो तत्समय प्रवृत्त दर पर उन पर देय उतकर दर्शाया जाएगा ।

6. मासिक विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना : (1) प्रत्येक विनिर्माता, इन नियमों के उपाबंध में विनिर्दिष्ट विनिर्माण, प्रत्येक मास के लिए, स्वयं हस्ताक्षर करके या किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर से, जिसे उसने इस अभिप्रायिकृत किया है, कलक्टर को, और उसकी एक-एक प्रतिलिपि तथा आयुक्त को, इस प्रकार से भेजेगा जिससे उस मास की, जिससे विवरणियां संबंधित हैं, समाप्ति से पंद्रह दिन के पश्चात् उनके पास पहुंच जाएं । उत्पादक 54 के साथ केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 54 के अधीन समुचित अधिकारी को सुसंगत मास के लिए प्रस्तुत की गई विवरणियों की एक प्रमाणित प्रतिलिपि भी भेजेगा ।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट विवरणी उत्पादक द्वारा उस विवरणी में निर्दिष्ट प्राधिकारी को रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजी जाएगी ।

(3) यदि कोई उत्पादक उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर विवरणी भेजने में असफल रहता है या ऐसी विवरणी भेजता है जिसके बारे में कलक्टर का यह विश्वास करने का कारण है कि वह सही नहीं है या त्रुटिपूर्ण है तो कलक्टर उत्पादक पर एक सूचना तामील करके उसके कारखाने में उत्पादित और वहां से हटाई गई जूट विनिमितियों की बाबत उसके सभी लेखे या उनमें से किसी को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है ।

7. विवरणियों का संशोधन : यदि विनिर्माता, विवरणी प्रस्तुत करने के पश्चात्, उसमें कोई त्रुटि या मिथ्या विवरण पाता है तो वह, कलक्टर की अनुज्ञा से, विवरणी में सभुचित परिवर्तन कर सकता है और उसे मांग की सूचना प्राप्त होने के पूर्व किसी भी समय कलक्टर के सनक्ष पुनः प्रस्तुत कर सकता है ।

8. कलक्टर/परिषद् का विनिर्माता के विनिर्माण अभिलेखों का निरीक्षण करने का अधिकार : (1) प्रत्येक विनिर्माता, कलक्टर या परिषद् द्वारा इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति को, उसके द्वारा रखी गई लेखा पुस्तकों और उत्पादन अभिलेखों का, उसके द्वारा प्रस्तुत की गई मासिक विवरणियों की शुद्धता का सत्यापन करने के प्रयोजन के लिए, निरीक्षण करने देगा ।

(2) यदि ऐसे निरीक्षण के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार को उपकर के रूप में उत्पादक से शोध्य कोई धनराशि निकलती है तो कलक्टर निरीक्षण पूरा होने के तीन मास के भीतर उसके संदाय के लिए मांग की सूचना जारी करेगा । संदाय ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर किया जाएगा ।

9. लेखा देने की रीति: अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन उद्ग्रहीत उपकर के आगम भारत की संविधान निधि में 'बृहत् शीर्षक 038-संघ उत्पाद-शुल्क के अधीन उपबृहत् शीर्षक घ-वस्तुओं पर उपकर के अधीनस्थ लघु लेखा 'शीर्षक जूट पर उपकर' के अधीन जमा किए जाएंगे और न्तीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्पत्ति विनियोजन के पश्चात्, ऐसी धन राशियों को जो वह ऐसे आगमों में से आवश्यक समझे, उनमें से संग्रहण के खर्च को काटने के पश्चात् परिषद् को सौंप सकती है।

10. संग्रहण के खर्च: केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क द्वारा संग्रहण लिए प्रसार्य खर्च केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क द्वारा इस प्रकार उद्ग्रहीत उपकर के आगमों के चार प्रतिशत से अधिक नहीं

11. वे संगठन जिनके द्वारा और वे प्रयोजन जिनके लिए, उपकर के आगमों का उपयोजन किया जाएगा: जूट विनिर्माण विकास परिषद् अधिनियम, 1983 (1983 का 27) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित की गई जूट विनिर्माण विकास परिषद् वह संगठन होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे मंजूर की गई उपकर निधि का

उपयोजन करेगा। निधि का उपयोजन निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा :—

- (क) जूट विनिर्माण विकास परिषद् अधिनियम, 1983 (1983 का 27) की धारा 7 में उपबंधित उपायों के खर्चों का वहन करने के लिए;
- (ख) परिषद् के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतनों, भत्तों और अन्य पारिश्रमिकों के व्ययों का वहन करने के लिए;
- (ग) परिषद् को चलाने और उसके कृत्यों के निर्वहन में होने वाले परिषद् के अन्य प्रशासनिक व्ययों का वहन करने के लिए, और
- (घ) जूट निधि की प्रतिभूति पर लिए गए, और जूट विनिर्माण विकास परिषद् अधिनियम, 1983 (1983 का 27) के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए जूट निधि में जमा किए गए, किन्हीं उधारों का प्रतिदाय करने के लिए।

[फा० सं० 5/16/83-ई पी (टी एण्ड जे)-III]
जे. के. बागची, संयुक्त सचिव

उपबन्ध

[नियम 6(1) देखिए]

जूट विनिर्माण उपकर नियम, 1984 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली मासिक विवरणी का प्रारूप को समाप्त होने वाले मास से तक के मौसम की विवरणी उत्पादक का नाम पता

कच्चे जूट का आदि स्टान		कच्चे जूट की प्राप्त की गई मात्रा		कुल उपलब्ध कच्चा जूट		उपयोग में लाया गया कुल कच्चा जूट	
विवरण	मात्रा (180 किलोग्राम के बलों में)	विवरण	मात्रा (180 किलोग्राम के बलों में)	विवरण	मात्रा (180 किलोग्राम के बलों में)	विवरण	मात्रा (180 किलोग्राम के बलों में)
1	2	3	4	5	6	7	8

उपकर के अधीन, विनिर्मित माल उपकर के अधीन, हटाया गया माल विनिर्मित अन्य माल, यदि कोई है विनिर्मित किन्तु रही हो गया या नष्ट हुआ माल, यदि कोई है

विवरण	मात्रा	विवरण	मात्रा	विवरण	मात्रा	विवरण	मात्रा
9	10	11	12	13	14	15	16
1.							
2.							
3.							

माल का अंत स्टॉक		मास के दौरान संदत्त उपकर की कुल रकम		टिप्पणियां
विवरण	मात्रा	मात्रा	रकम (रुपयों में)	
17	18	19	20	21
1.				
2.				
3.				

टिप्पण :

1. प्रयोग में लाए गए कच्चे जूट की प्रत्येक किस्म/श्रेणी की और उत्पादित तथा हटाए गए तैयार माल की प्रत्येक किस्म की पृथक विवरणियां प्रस्तुत की जानी चाहिए।

2. रद्द होने या नष्ट होने के कारण 'टिप्पणियां' के स्तम्भ में उपदर्शित किए जाने चाहिए।

मैं/हम घोषित करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने ऊपर दर्शाई गई विवरणियों की तुलना अपने कारखाने के अभिलेखों और पुस्तकों से कर ली है और ये, जहां तक कि मैं/हम विनिश्चित कर सका हूँ/सके हैं, वे सही और पूर्ण हैं।

तारीख :

स्थान :

उत्पादक के हस्ताक्षर

नाम (स्पष्ट अक्षरों में)

पदनाम

NOTIFICATION

The Jute Manufactures Cess Rules, 1984

G.S.R. 659(E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Jute Manufacture Cess Act, 1983, (28 of 1983) the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title.—(1) These rules may be called the Jute Manufactures Cess Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions:—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Jute Manufactures Cess Act, 1983 (28 of 1983);

(b) "Cess" means the duty of excise levied under sub-section (1) of section 3 of the Act;

(c) "Collector" means the Collector of Central Excise appointed under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and includes an Additional Collector of Central Excise, Deputy Collector of Central Excise, Assistant Collector of Central Excise and Superintendent of Central Excise;

(d) "Commissioner" means the Jute Commissioner of the Government of India and includes the Deputy Jute Commissioner, Industrial Adviser and Deputy Director in the Office of the Jute Commissioner;

(e) "Producer", in relation to a jute manufacture, means the producer of such jute manufactures;

(f) "Council" means the Jute Manufacturers Development Council set up under sub-section (1) of section 3 of the Jute Manufacturers Development Council Act, 1983 (27 of 1983);

(g) "Jute Fund" means the Fund created under sub-section (1) of section 10 of the Jute Manufacturers Development Council Act, 1983 (27 of 1983);

(h) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) or the rules made thereunder shall have the same meanings, respectively assigned to them in that Act or the rules.

3. Rate of Cess:—Cess shall be payable at the rate specified by the Central Government in accordance with the Act from time to time on finished jute manufactures removed for sale subsequent sale by the producer for export abroad and/or for distribution and consumption within the country.

4. No refund of Cess on account of Exports:—No refund of cess shall be allowed on the jute manufactures exported from India.

5. Maintenance of Register:—Every producer shall maintain a register of production indicating therein the total quantity of jute manufactures manufactured by him during a month, the quantity (if any) used by him for the manufacture of any other commodity, the quantity removed on payment of duty under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the quantity removed for export without payment of such duty, the total value ad valorem and the cess payable thereon at the rate for the time being in force.

6. Submission of monthly returns.—(1) Every producer shall furnish to the Collector, with a copy each to the Council and the Commissioner, the particulars specified in the Annexure to these rules, for each month, duly signed by the producer or any other person authorised by him in this behalf, so as to reach them not later than fifteen days after the expiry of the month to which the return relates, alongwith a certified copy of the returns submitted to the proper officer under rule 54 of the Central Excise Rules, 1944 for the relevant month.

(2) The return referred to in sub-rule (1) shall be furnished by the producer to the authorities referred to therein by registered post with acknowledgment due.

(3) If any producer fails to furnish the return within the date specified in sub-rule (1) or furnishes a return which the Collector has reason to believe is incorrect or defective, the Collector may serve a notice on the producer calling upon him to produce all or any of his accounts relating to the jute manufactures produced in and removed from his factory.

7. Revision of returns.—If the producer, after furnishing a return, discovers any omission or wrong statement therein, he may with the permission of the Collector, make appropriate changes in the return

and re-submit it to the Collector at any time before he receives the notice of demand.

8. Right of the Collector/Council to inspect the production records of the producer:—(1) Every producer shall permit any person authorised in writing in this behalf by the Collector or the Council to inspect the books of account and records of production maintained by him for the purpose of verifying the correctness of the monthly returns furnished by him.

(2) If as a result of such inspection any sum of money is found to be due to the Central Government from the producer by way of cess, the Collector may within three months of completion of the inspection, issue a notice of demand for the payment thereof within a month from the date of receipt of such notice.

9. Manner of Accounting:—The proceeds of the cess levied under sub-section (i) of section 3 of the Act, shall be credited to the Consolidated Fund of India under the Minor Head "Cess on Jute—Subordinate Major Head D—Cess on commodities under the Minor Head 1038—Union Excise Duties" and the Central Government may, after due appropriation made by Parliament by law in this behalf, handover to the Council such sums, as it may consider necessary from out of such proceeds after deducting therefrom the cost of collection.

10. Cost of Collection:—The cost of collection chargeable by the Central Excise shall not exceed four per cent of the proceeds of cess so collected by the Central Excise.

11. Organisation by which, and purposes for which the proceeds of the cess shall be utilised:—

The Jute Manufacturers Development Council set up under sub-section (i) of Section 3 of the Jute manufactures Development Council Act, 1983 (27 of 1983) shall be the organisation for utilisation of the cess fund so granted to it by the Central Government. The fund shall be utilised for:

- (a) meeting the cost of the measures provided in section 7 of the Jute Manufacturers Development Council Act, 1983 (27 of 1983);
- (b) meeting expenses on the salaries, allowances and other remuneration of the officers and other employees of the Council;
- (c) meeting the other administrative expenses of the Council as may be involved in running the Council and in the discharge of its functions; and
- (d) repayment of any loans taken on the security of the Jute Fund, and credited to the Jute Fund for carrying out the purposes of the Jute Manufacturers Development Council Act, 1983 (27 of 1983).

ANNEXURE

[See rule 6(i)]

FORM OF MONTHLY RETURN TO BE SUBMITTED UNDER THE JUTE MANUFACTURES CESS RULES, 1984

Month ending.....Season from.....to.....
 Name of producer.....
 Address.....

Opening stock of raw jute		Quantity of raw jute received		Total available raw jute		Total raw jute consumed	
Description	Quantity (In bales of 180 Kilograms)	Description	Quantity (In bales of 180 Kilograms)	Description	Quantity (In bales of (180 Kilograms)	Description	Quantity (In bales of 180 Kilograms)
1		3	4	5	6	7	8

1.
2.
3.
4.
5.

Goods, subject to Cess, manufactured		Goods, subject to Cess, removed		Other goods manufactured, if any	
Description	Quantity	Description	Quantity	Description	Quantity
9	10	11	12	13	14

1.
2.
3.
4.
5.

Goods manufactured but wasted or destroyed, if any		Closing Stocks of Goods		Total amount of cess paid during the month		Remarks
Description	Quantity	Description	Quantity	Description	Amount (In Rs.)	
15	16	17	18	19	20	21

1.
2.
3.
4.
5.

Note : —1. Separate particulars of each variety/grade of raw jute used and each variety of finished goods produced and removed should be furnished.

2. The reason for wastage and destruction should be indicated in the 'Remarks' column.

I/We declare that I/we have compared the above shown particulars with the records and books of my/our factory and that they are, in so far as I/We can ascertain, accurate and complete.

Date.....
 Place.....

Signature of producer.
 Name (in capital letters)
 Designation.....